

प्रारंभिक परीक्षा

भारत सरकार ने गूगल टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया

संदर्भ

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्लाइजेशन (समकारी) लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है।

इक्लाइजेशन लेवी (EL) क्या है?

- इक्लाइजेशन लेवी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका उद्देश्य निवासी और गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों के कर घटक को 'बराबर' करना है।
- इसकी शुरुआत 2016 में की गयी थी और इसने शुरू में अपतटीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल विज्ञापनों पर 6% कर लगाया था।
- इक्लाइजेशन लेवी के लिए पात्र होने हेतु दो शर्तें पूरी होनी चाहिए:
 - भुगतान किसी अनिवासी सेवा प्रदाता को किया जाना चाहिए।
 - यदि एक वित्तीय वर्ष में एक सेवा प्रदाता को किया गया वार्षिक भुगतान 1,00,000 रुपये से अधिक है।
- इसे अनौपचारिक रूप से "गूगल टैक्स" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह गूगल, मेटा और अमेज़ॉन जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें इस कर को रोकना पड़ता है और भारत सरकार को भेजना पड़ता है।

सरकार का इक्लाइजेशन लेवी समाप्त करने का प्रस्ताव -

- वित्त विधेयक, 2025 में 35 संशोधनों के हिस्से के रूप में, डिजिटल विज्ञापनों पर 6% इक्लाइजेशन लेवी 1 अप्रैल, 2025 से समाप्त कर दिया जाएगा।
- यह कदम 2024 में ई-कॉमर्स पर 2% इक्लाइजेशन लेवी को निरस्त करने के बाद उठाया गया है।

स्रोत:

- [Indian Express - Equalisation Levy](#)

स्वर्ण मुद्रिकरण योजना (Gold Monetisation Scheme)

संदर्भ

भारत सरकार ने स्वर्ण मुद्रिकरण योजना (गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम) के अंतर्गत मध्यम अवधि और दीर्घकालिक जमा (MLTGD) को बंद करने का निर्णय लिया है।

स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के बारे में -

- स्वर्ण मुद्रिकरण योजना (GMS) को पुरानी स्वर्ण जमा योजना के संशोधित संस्करण के रूप में नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था।
- स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के उद्देश्य:
 - निष्क्रिय सोने का उपयोग करना – व्यक्तियों और संस्थाओं को अपना सोना बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
 - सोने के आयात को कम करना – आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू सोने की उपलब्धता बढ़ाना।
 - सोने की जमाराशि पर ब्याज प्रदान करना – सोने को निष्क्रिय रखने के बजाय उस पर रिटर्न प्रदान करना।
 - आभूषण उद्योग को समर्थन - बैंकों को आभूषण निर्माताओं को सोना उधार देने की अनुमति देना, जिससे क्षेत्र में तरलता बढ़ेगी।
- इस योजना में तीन जमा विकल्प थे:
 - अल्पावधि बैंक जमा (STBD): 1-3 वर्ष (ब्याज बैंकों द्वारा तय और वहन किया जाएगा)।
 - मध्यावधि सरकारी जमा (MTGD): 5-7 वर्ष (ब्याज सरकार द्वारा तय और वहन किया जाएगा)।
 - दीर्घावधि सरकारी जमा (LTGD): 12-15 वर्ष (ब्याज सरकार द्वारा तय और वहन किया जाएगा)।

स्वर्ण मुद्रिकरण योजना की चुनौतियाँ -

- कम भागीदारी: भारतीय वित्तीय स्वर्ण उत्पादों की तुलना में भौतिक सोना रखना पसंद करते हैं।
- विश्वास संबंधी मुद्दा: लोग पारिवारिक विरासत और आभूषण को जमा करने में झिझकते हैं।
- भंडारण और तरलता: बैंकों को एकत्रित सोने का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सॉवरेन गोल्ड बांड का बंद होना -

- सॉवरेन गोल्ड बांड (SGBs) जारी करने पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के बाद, यह हाल ही में बंद की जाने वाली दूसरी स्वर्ण-संबंधी योजना है।
- सॉवरेन गोल्ड बांड योजना के तहत, निवेश के समय धातु के मूल्य के आधार पर ब्याज के साथ 5-7 वर्षों के लिए 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम मूल्यवर्ग में बांड जारी किए गए थे।
- इस योजना में प्रति व्यक्ति 500 ग्राम की वार्षिक सीमा थी।
- सरकार सोने से संबंधित निवेश योजनाओं से पीछे हट रही है, संभवतः सोने की बढ़ती कीमतों और बाजार की स्थितियों के कारण।

स्रोत:


- [Indian Express - GMS](#)

समाचार संक्षेप में

सरकार ने MSME के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए

- केंद्र सरकार ने MSME को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

REVISED DEFINITION OF MSMEs



Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

MSME के लिए सरकार की पहल -

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा के साथ 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे।
- निर्यात संवर्धन मिशन निर्यात ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और MSME को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने में सहायता करेगा।
- स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा।
- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को सामूहिक या क्लस्टरों में संगठित करना, उत्पाद विकास, विविधीकरण और मूल्य संवर्धन को सुविधाजनक बनाना है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।

स्रोत:

- [News on Air- MSME](#)

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)

- यह एक एआई-आधारित प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगा।
- इसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था।

- **उद्देश्य:** उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके पूरे भारत में कीट रोगों की निगरानी और प्रबंधन को बढ़ाना।
- **NPSS की मुख्य विशेषताएं:**
 - कीट पहचान और प्रबंधन:
 - किसान 61 विभिन्न फसलों में कीटों और बीमारियों की पहचान कर सकते हैं।
 - यह 15 प्रमुख फसलों के लिए कीट प्रबंधन सलाह प्रदान करता है।
 - बहुभाषी समर्थन: NPSS चार भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और पंजाबी में उपलब्ध है।
 - रीयल-टाइम सलाह प्रणाली: किसानों को कीट हमलों, फसल रोगों और फसल के नुकसान के बारे में तुरंत समाधान मिलता है।
 - प्रयुक्त तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल)।

स्रोत:

- [PIB - NPSS](#)

रुशिकोंडा/रुषिकोंडा समुद्री तट ने ब्लू फ्लैग टैग वापस जीता

- रुशिकोंडा समुद्री तट ने ब्लू फ्लैग टैग वापस जीता, जिसे पहले खराब रखरखाव के कारण वापस ले लिया गया था।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) क्या है?

- ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय इको-लेबल है, जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE), डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह समुद्री तटों, मरीन और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को दिया जाता है, जो उच्च पर्यावरण, सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को पूरा करते हैं।
- **मानदंड:** ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने के लिए, एक समुद्र तट को चार प्रमुख श्रेणियों में 33 कड़े मानदंडों को पूरा करना होता है:
 - पर्यावरण शिक्षा और सूचना।
 - जल गुणवत्ता।
 - पर्यावरण प्रबंधन।
 - सुरक्षा और सेवाएँ।
- भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट हैं।

स्रोत:

- [The Hindu - Blue Flag Beaches](#)



समाचार में स्थान

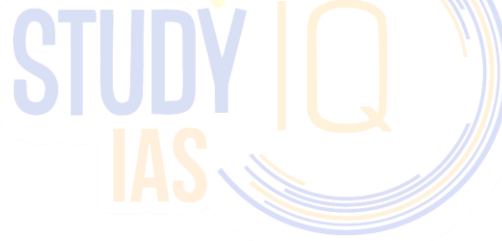
काला सागर

- रूस और यूक्रेन ने काला सागर में और ऊर्जा अवसंरचना पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है।
- यह समझौता सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान हुआ।



- यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित एक बड़ा अंतर्देशीय सागर है।
- यह बोस्फोरस जलडमरूमध्य, मरमारा सागर और डार्डनेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- काला सागर की सीमा से लगे देश: तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और रोमानिया। (याद रखने की ट्रिक- T-BURGeR)
- काला सागर में बहने वाली नदियाँ: डेन्यूब, नीपर, डॉन।

स्रोत: [The Hindu - Black sea](#)



संपादकीय सारांश

एआई, UBI, इन दोनों के बीच

संदर्भ

बिल गेट्स का समग्र दृष्टिकोण यह है कि **एआई UBI** को **व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त धन और दक्षता उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रभावी नीति, कराधान और धन पुनर्वितरण रणनीतियों की आवश्यकता होगी।**

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) या सार्वभौमिक बुनियादी आय क्या है?

- **UBI से तात्पर्य सरकार (या किसी अन्य संस्था) द्वारा सभी नागरिकों को रोजगार की स्थिति या आय के स्तर की परवाह किए बिना किया जाने वाले नियमित बिना शर्त भुगतान से है।**
- **मूल सिद्धांत:**
 - **बिना शर्त:** कार्य या आय स्तर से संबंधित कोई आवश्यकता नहीं।
 - **सार्वभौमिक:** सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध, न कि केवल विशिष्ट समूहों के लिए।
 - **आवधिक:** नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाता है (मासिक, वार्षिक)।
 - **नकद आधारित:** वस्तुओं या सेवाओं के बजाय नकद में दिया जाता है।

UBI पर एआई के सकारात्मक प्रभाव -

- **धन सृजन में वृद्धि:** एआई-संचालित स्वचालन और उत्पादकता महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य का सृजन कर सकती है, जिसे **UBI** के माध्यम से पुनर्वितरित किया जा सकता है।
 - विनिर्माण, वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उच्च दक्षता से समग्र सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे **UBI** वित्तपोषण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
- **जीवन-यापन की लागत में कमी:** AI स्वचालन और व्यक्तिगत AI समाधानों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानूनी सहायता) की लागत को कम कर सकता है।
 - जीवन-यापन की लागत कम होने से बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक **UBI** की राशि कम हो जाएगी।
- **एआई कराधान के माध्यम से वित्तपोषण:** सुपर-प्रॉफिट उत्पन्न करने वाली एआई-संचालित कंपनियों पर **UBI** के लिए एक स्थायी वित्तपोषण स्रोत बनाने के लिए कर लगाया जा सकता है।
 - एआई-आधारित स्वचालन और बौद्धिक संपदा पर कर लगाने से **UBI** के लिए एक स्थिर राजस्व प्रवाह उपलब्ध हो सकता है।
- **नए आर्थिक मॉडल का निर्माण:** एआई संप्रभु एआई मॉडल को सक्षम कर सकता है, जहां सरकारें एआई प्रणालियों का स्वामित्व रखती हैं और व्यवसायों को पट्टे पर देती हैं, जिससे **UBI** के लिए आय उत्पन्न होती है।
 - एआई-आधारित उत्पादकता उपकरण सार्वजनिक स्वामित्व में हो सकते हैं, जिससे नागरिक एआई-संचालित लाभ से लाभांश अर्जित कर सकेंगे।
- **रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों के लिए अधिक समय:** पारंपरिक कार्य की आवश्यकता को कम करके, एआई लोगों को कला, अनुसंधान, सामाजिक कार्य और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है।
 - श्रम-पश्चात अर्थव्यवस्था नए सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलनों को जन्म दे सकती है।
- **बुद्धिमत्ता का लोकतंत्रीकरण:** एआई उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता को बहुत कम या बिना किसी लागत के व्यापक रूप से सुलभ बना सकता है।
 - एआई-संचालित सेवाओं तक अधिक पहुंच से सामाजिक असमानता कम हो सकती है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

एआई और UBI के नकारात्मक प्रभाव -

- **धन और शक्ति का संकेन्द्रण:** वर्तमान में AI विकास और स्वामित्व पर कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों का प्रभुत्व है।
 - यदि एआई-जनित धन संकेन्द्रित रहा तो असमानता सुधरने के बजाय और भी खराब हो सकती है।
- **सफेदपोश नौकरियों का विस्थापन:** एआई द्वारा शारीरिक श्रम से पहले जटिल संज्ञानात्मक नौकरियों (जैसे, कानूनी, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्र) को स्वचालित करने की संभावना है।
 - इससे संरचनात्मक बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।
- **सरकार और निगमों पर निर्भरता:** यदि AI धन को UBI के माध्यम से पुनर्वितरित किया जाता है, तो लोग राज्य या कॉर्पोरेट नीतियों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं।
 - राजनीतिक अस्थिरता या कॉर्पोरेट विफलताएं आजीविका को खतरे में डाल सकती हैं।
- **उद्देश्य और पहचान की हानि:** कार्य संरचना, पहचान और सामाजिक मान्यता प्रदान करता है।
 - यदि एआई काम की आवश्यकता को समाप्त कर दे, तो अनेक व्यक्ति अर्थ और उद्देश्य की कमी से जूझ सकते हैं।
- **नैतिक और नियामक चुनौतियाँ:** यह निर्धारित करना कि एआई द्वारा उत्पन्न धन पर किस प्रकार कर लगाया जाए तथा उसका उचित तरीके से पुनर्वितरण किया जाए, राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो सकता है।
 - एआई स्वामित्व और **UBI** वितरण के लिए नियामक ढांचे जटिल और क्रियान्वयन में कठिन हो सकते हैं।
- **वैश्विक असमानता का जोखिम:** जबकि एआई उपकरण अधिक सुलभ होते जा रहे हैं, आधारभूत एआई अनुसंधान और बुनियादी ढांचा अभी भी पश्चिम और चीन में ही केंद्रित है।
 - विकासशील देशों को एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह -

- **नीति और विनियमन**
 - एआई-जनित धन पर कर लगाने के लिए कानूनी ढांचा विकसित करना।
 - सभी नागरिकों के लिए एआई-संचालित सेवाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना।
- **प्रयोग और पायलट**
 - **UBI** पर पायलट कार्यक्रम आयोजित करना (जैसे फिनलैंड का 2017-18 का प्रयोग)।
 - वित्तपोषण और वितरण के विभिन्न मॉडलों का परीक्षण करना।
- **सार्वजनिक एआई अवसंरचना में निवेश**
 - सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रूप में संप्रभु एआई मॉडल विकसित करना।
 - व्यापक पहुंच के लिए ओपन-सोर्स एआई विकास को प्रोत्साहित करना।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी**
 - उद्देश्य की वैकल्पिक संरचनाओं को बढ़ावा दें (कला, देखभाल, स्वयंसेवा)।
 - कार्य-आधारित पहचान के स्थान पर सामुदायिक और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करना।
- **समतामूलक एआई शासन**
 - एआई बुनियादी ढांचे और लाभों पर एकाधिकार को रोकना।
 - एआई नैतिकता और धन वितरण पर वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **एआई-संचालित कौशल परिवर्तन**
 - आजीवन सीखने और एआई उपकरणों के अनुकूलन को प्रोत्साहित करना।
 - एआई-आधारित उद्योगों में पुनः कौशल विकास और उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाना।

स्रोत: [Indian Express: AI, UBI, in Between](#)

विस्तृत कवरेज

बुलडोजर न्याय

संदर्भ

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बुलडोजर न्याय' के रूप में जाना जाता है।

हाल के उदाहरण -

- बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की आलोचना करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो से जुड़े एक "अनधिकृत" शेड को ध्वस्त कर दिया।
- मालवन नगर परिषद ने एक परिवार के घर को ध्वस्त कर दिया, जिसके 14 वर्षीय बच्चे ने कथित तौर पर क्रिकेट मैच के दौरान "भारत विरोधी" नारे लगाए थे।
- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में शहर में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी, लेकिन प्रमुख ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए आदेश बहुत देर से आया।

बुलडोजर न्याय (या न्यायेतर-कानूनी विध्वंस) क्या है?

यह त्वरित न्याय तंत्र को संदर्भित करता है जिसे विभिन्न राज्यों की सरकारें कथित दंगाइयों, प्रदर्शनकारियों या गंभीर अपराध करने वालों को जेसीबी मशीन का उपयोग करके उनके घरों, स्टॉल या किसी भी निर्माण को ध्वस्त करके दंडित करने के लिए प्रचारित करती हैं।

TIMELINE

Sept 6, 2017

Yogi Adityanath announces for the first time that his govt will raze houses of those involved in criminal activities

July 5, 2020

UP officials demolish the house of dreaded criminal Vikas Dubey whose accomplices shot dead eight policemen

August 27, 2020

UP authorities demolish two illegal buildings owned by gangster-turned-politician Mukhtar Ansari in Lucknow's posh Dalibagh area

Sept 23, 2020

A joint team of the Prayagraj Development Authority, district administration and

police, demolishes a house belonging to former parliamentarian Atiq Ahmed here as part of its drive against the jailed mafia don's unauthorised properties

March 21, 2022

After the violence in Madhya Pradesh's Raisen, the district administration pulls down illegal homes and shops of the alleged culprits

March 22, 2022

The house of the main accused of the gang rape of a 28-year old demolished in Shahdol district

April 12, 2022

A day after communal clashes in Madhya Pradesh's Khargone,

16 houses and 29 shops, mostly owned by Muslims, razed citing their involvement in the riots

June 14, 2022

Kanpur house of Mohammad Javed, a political activist and businessman, pulled down after serving just a day's notice to vacate it

April 20, 2022

North Delhi Municipal Corporation demolishes several structures in the violence-hit Jahangirpuri; SC orders stay

April 21, 2022

SC hears petition filed by Jamiat-Ulama-i-Hind against demolition drive in Jahangirpuri

July 5, 2023

Bulldozer action against a man who urinated on a tribal

Dec 14, 2023

10 meat shops and houses of three persons accused of attacking a BJP worker demolished in Bhopal

August 23, 2023

Congress leader Shahzad Ali's property in Chhatarpur demolished for allegedly leading a protest demanding action against a person for blasphemous remarks

June 15, 2024

Houses of 11 demolished after police find beef in their refrigerators in tribal-dominated Mandla in Madhya Pradesh

बुलडोजर न्याय के लिए औचित्य -

- **कानूनी औचित्य:** राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि- अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई या अनधिकृत निर्माण के बहाने से नगरपालिका कानून के अंतर्गत तोड़फोड़ किया जाना उचित है।
 - **उदाहरण के लिए-** ध्वस्तीकरण के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम का प्रयोग किया गया।
- **सार्वजनिक व्यवस्था और रोकथाम बनाए रखना:** दुर्दांत अपराधियों के मन में कानून के प्रति भय उत्पन्न करना।
- **व्यवस्था पुनर्स्थापित करना:** राज्य सरकारों का तर्क है कि- सांप्रदायिक संघर्षों में आरोपियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने से, व्यवस्था पुनर्स्थापित करने एवं हिंसा के दौरान तनाव कम करने में सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए- नूंह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने ऐसा ही किया।
- **स्पष्ट प्रयोजन:** भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में की गई तोड़फोड़ का उद्देश्य, किसी विशिष्ट अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि विभिन्न समुदायों के लोगों की संपत्ति को प्रभावित करना था, क्योंकि इसका उद्देश्य अतिक्रमण को हटाना था।
- **अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराने का तरीका:**
 - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अभियान से राजस्व विभाग को भू-माफियाओं से लगभग **67,000** एकड़ भूमि मुक्त कराने में सहायता मिली एवं अधिग्रहित भूमि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया।

बुलडोजर न्याय से संबंधित मुद्दे -

- **विधि के शासन के विरुद्ध, विधि की उचित प्रक्रिया-** बिना नोटिस दिए अपराध के आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों को गिराना, विधि के शासन का उल्लंघन है और यह विधि के शासन (अनुच्छेद 14) की भावना तथा अनुच्छेद 21 के तहत मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखी गई विधि की उचित प्रक्रिया के विरुद्ध है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- **शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध-** अभियुक्त का अपराध न्यायालय के समक्ष सिद्ध होना चाहिए तथा दण्ड न्यायपालिका द्वारा दिया जाना चाहिए, न कि कार्यपालिका द्वारा, क्योंकि यह सामूहिक न्यायेतर दण्ड के समान है।
- **बुलडोजर न्याय पर न्यायपालिका का अवलोकन**
 - **2024** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कहा, "नागरिक अधिकारियों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करना, फैशन बन गया है।"
 - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया की कमी एवं जातीय लक्ष्यीकरण की संभावना पर चिंताओं का संदर्भ देते हुए, नूंह में विध्वंस को रोकने के लिए कदम उठाया।
 - **सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने कहा:**
 - किसी व्यक्ति की अपराध में कथित संलिप्तता, संपत्ति को ध्वस्त करने का कारण नहीं हो सकती है, उन्होंने कहा कि- ऐसी कार्रवाई को "देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने" के रूप में देखा जा सकता है।
 - कोर्ट ने यह भी कहा कि- परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया उल्लंघन, परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित नहीं कर सकता।
 - किसी अपराध में कथित संलिप्तता के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना उचित नहीं है, क्योंकि कथित अपराध को न्यायालय में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, 1985:** सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया के महत्व पर बल दिया तथा निर्णय सुनाया कि- बिना नोटिस के बेदखली, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।
- **नगर निगम लुधियाना बनाम इंद्रजीत सिंह, 2008:** नोटिस दिए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना, अवैध निर्माण को भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
- **सुदामा सिंह और अन्य बनाम दिल्ली सरकार तथा अजय माकन एवं अन्य बनाम भारत संघ:** इन मामलों में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने की परिकल्पना की गई थी।

- **आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रतिकूल:** सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना, देश की न्यायपालिका एवं संविधान में विश्वास की कमी को दर्शाता है, जिससे नागरिकों को गलत संकेत मिलता है।
- **विशिष्ट समूहों को लक्षित करना:** इसकी भी आलोचना की जाती है कि, विध्वंस न्याय में लोगों को उनकी जाति/समुदाय के आधार पर निशाना बनाया जाता है।
- **एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड:** अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि- किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए विध्वंस के माध्यम से दोषी को फिर से दंडित करना, मूल अधिकार की भावना के विरुद्ध है, जो दोहरे खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **संपत्ति का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक कानूनी अधिकार है:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि, किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- **विध्वंस-पूर्व सर्वेक्षण एवं अग्रिम सूचना-** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि- किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले सर्वेक्षण अवश्य किया जाना चाहिए एवं प्राधिकारियों को पर्याप्त अग्रिम सूचना देने सहित, बुनियादी प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
- विध्वंस प्रक्रियाओं पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को स्थानीय नगरपालिका कानूनों तथा विनियमों में एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विध्वंस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में- विध्वंस से पहले, उसके दौरान और उसके बाद, सही प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
- ओल्गा टेलिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, विध्वंस से पहले सख्त कानूनी अनुपालन आवश्यक है।
- आश्रय के मानव अधिकार की बेहतर सुरक्षा हेतु विध्वंस के लिए साक्ष्य का भार प्राधिकारियों पर डाला जाना चाहिए, जिसे चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र:** न्यायाधीशों और नागरिक समाज के सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिए, जो यह जांच करे कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कानूनी है या नहीं।
- **दण्ड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए:** एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं होना चाहिए तथा दंडात्मक उपायों का उद्देश्य दोषियों को सुधारना होना चाहिए।

स्रोत: [Indian Express: Injustice Unchecked](#)